

## Weekly One Liners 30<sup>th</sup> June to 6<sup>th</sup> July, 2025

### RailOne App लॉन्च: भारतीय रेलवे ने यात्री सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म के तहत एकीकृत किया

रेलवे सेवाओं में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 जुलाई, 2025 को 'रेलवन' मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया। एक व्यापक, वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित, ऐप यात्रियों को टिकट बुकिंग, पीएनआर पूछताछ, यात्रा योजना, भोजन बुकिंग और माल ढुलाई पूछताछ जैसी सेवाओं तक एकीकृत पहुंच प्रदान करता है, जिससे लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा और डिजिटल अनुभव बढ़ जाता है।

#### समाचार में क्यों?

2 जुलाई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 'RailOne' मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। यह ऐप रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS) की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च किया गया। यह एक सिंगल प्लेटफॉर्म समाधान है, जो यात्रियों और माल ढुलाई ग्राहकों दोनों के लिए रेलवे की तमाम डिजिटल सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है।

#### RailOne ऐप के प्रमुख उद्देश्य:

- यात्रियों के लिए सुविधाजनक, सुरक्षित और डिजिटल यात्रा अनुभव प्रदान करना।
- रेलवे की सभी सेवाओं को एकीकृत कर एक ऐप में उपलब्ध कराना।
- डिजिटल इंडिया मिशन और रेलवे की स्मार्ट ट्रेवल विज़न के अनुरूप तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना।

#### RailOne ऐप की प्रमुख विशेषताएं:

##### यात्रियों के लिए सेवाएं:

- आरक्षित और अनारक्षित टिकट बुकिंग
- PNR स्टेटस और ट्रेन पूछताछ
- यात्रा योजना (Journey Planning)
- प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग
- ट्रेन में भोजन बुकिंग (Meal Booking)
- रेल हेल्प सेवाएं
- मालभाड़ा (Freight) पूछताछ



#### यूजर इंटरफेस और लॉगिन सुविधा:

- सरल, साफफ्रेंडली डिज़ाइन-सुथरा और यूजर-
- Single Sign-On:** पहले से मौजूद RailConnect या UTSonMobile लॉगिन से सीधा उपयोग
- कम ऐप की ज़रूरत, स्टोरेज की बचत
- मेमोरी फ्रेंडली और तेज़ नेविगेशन

#### अतिरिक्त सुविधाएं:

- R-Wallet (रेलवे ई-वॉलेट) से सुरक्षित और तेज़ भुगतान
- बायोमेट्रिक लॉगिन और mPIN सुरक्षा प्रणाली
- त्वरित पंजीकरण, न्यूनतम जानकारी के साथ
- गेस्ट लॉगिन: मोबाइल नंबर और OTP के ज़रिए बिना रजिस्ट्रेशन के पूछताछ

#### पृष्ठभूमि और दृष्टिकोण:

- रेल मंत्रालय द्वारा विकसित, CRIS के सहयोग से
- डिजिटल इंडिया अभियान के तहत भारत की रेल सेवाओं को आधुनिक बनाने की पहल
- एक समेकित (Unified) डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में भारतीय रेलवे की सेवाओं को एकीकृत करना

#### महत्वपूर्ण प्रभाव:

- 23 करोड़ से अधिक दैनिक यात्रियों के लिए सुविधा में बढ़ोतरी
- योजना बनाने में पारदर्शिता और समय की बचत
- यात्रा अनुभव को स्मार्ट और डिजिटल बनाना
- मल्टीपल ऐप्स की आवश्यकता खत्म, सब कुछ एक ही स्थान पर
- युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीण यात्रियों के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी में बढ़ावा

#### उपलब्धता:

Android Play Store और iOS App Store पर RailOne ऐप अब डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

### केबिनेट ने भारत भर में 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा करने के लिए ईएलआई योजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है (ईएलआई), जिसका लक्ष्य विनिर्माण पर विशेष जोर देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा करना है। लगभग ₹1 लाख करोड़ के पर्याप्त परिव्यय के साथ, इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार को बढ़ावा देना, नए रोजगार सृजित करने में नियोक्ताओं का समर्थन करना और भारत के युवा कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है।

#### समाचार में क्यों?

1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगारआधारित प-्रोत्साहन (ELI) योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक औपचारिक नौकरियां सृजित करना है, विशेषकर विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र पर जोर देते हुए। यह योजना 2024-25 के केंद्रीय बजट में घोषित ₹2 लाख करोड़ के रोजगार व कौशल पैकेज का हिस्सा है।

**उद्देश्य और लक्ष्य:**

- 3.5 करोड़ औपचारिक रोजगार का सृजन (1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक)।
- पहली बार नौकरी पाने वालों को प्रोत्साहन देना।
- EPFO पंजीकरण के ज़रिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाना।
- विनिर्माण, सेवा व अन्य क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देना।
- वित्तीय साक्षरता और बचत संस्कृति को युवाओं में प्रोत्साहित करना।

**ELI योजना की संरचना:**

**Part A - पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन:**

- **लाभार्थी:** 1.92 करोड़ नए कर्मचारी जो EPFO में पंजीकृत हैं।
- **लाभ:** अधिकतम ₹15,000 तक की एक महीने की मजदूरी, दो किस्तों में:
  - पहली किस्त :6 महीने की सेवा के बाद
  - दूसरी किस्त :12 महीने की सेवा और वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण पूर्ण होने पर
- **योग्यता:** मासिक वेतन ₹1 लाख तक
- **नकद लाभ का एक हिस्सा सुरक्षित बचत साधनों में लॉक किया जाएगा।**

**Part B - नियोक्ताओं को समर्थन:**

- सभी क्षेत्रों में लागू पर मैनुफैक्चरिंग के लिए विशेष लाभ।
- **नियोक्ता की पात्रता:** EPFO में पंजीकृत होना अनिवार्य।
- **न्यूनतम नई भर्तियां:**
  - <50 कर्मचारी वाले फर्मों के लिए कम से कम :2 नई भर्तियां
  - ≥50 कर्मचारी वाले फर्मों के लिए कम से कम :5 नई भर्तियां

**नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन संरचना:**

कर्मचारी का मासिक वेतन (EPF वेज)	नियोक्ता प्रोत्साहन/माह
₹10,000 तक	₹1,000 तक
₹10,001 - ₹20,000	₹2,000
₹20,001 - ₹1,00,000	₹3,000

मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी जारी रहेगा।

**भुगतान तंत्र:**

- **Part A:** लाभार्थियों को DBT (आधार आधारित भुगतान प्रणाली) के ज़रिए सीधे भुगतान।
- **Part B:** नियोक्ताओं को उनके PAN-लिंकड खाते में भुगतान।

**महत्वपूर्ण प्रभाव:**

- COVID-19 के बाद युवाओं के लिए बड़ी संख्या में औपचारिक नौकरियों का सृजन।
- EPFO पंजीकरण को प्रोत्साहन देकर सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी।
- मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को बढ़ावा मिलेगा।
- नियोक्ताओं में जवाबदेही और युवाओं में वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा।
- आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता को बल मिलेगा।

**केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ₹1 लाख करोड़ की आरडीआई योजना को मंजूरी दी**

भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की एक बड़ी पहल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2025 को ₹1 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ अनुसंधान विकास और नवाचार योजना को मंजूरी दी। (आरडीआई) यह योजना उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, विशेष रूप से उभरते और रणनीतिक क्षेत्रों में, कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालिक वित्तपोषण की पेशकश करके। कार्यक्रम को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा रणनीतिक रूप से निर्देशित किया जाएगा। (एएनआरएफ)

**समाचार में क्यों?**

1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना को मंजूरी दी, जिसकी कुल लागत ₹1 लाख करोड़ है। इस योजना का उद्देश्य सूर्योदय क्षेत्रों (sunrise sectors) और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र द्वारा अनुसंधान और विकास (R&D) में निवेश को प्रोत्साहित करना है। इस योजना को अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (ANRF) की निगरानी में लागू किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे।

**योजना के प्रमुख उद्देश्य:**

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर्स, हरित ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में निजी R&D को बढ़ावा देना।
- तकनीक अधिग्रहण और व्यावसायीकरण में निवेश को प्रोत्साहित करना।
- उच्च **Technology Readiness Level (TRL)** परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देना।
- राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े रणनीतिक क्षेत्रों को समर्थन देना।
- एक **Deep-Tech Fund of Funds** की स्थापना जिससे नवाचार को दीर्घकालिक पूंजी सहायता मिले।

**दोस्तरीय संरचना-**

**Tier 1 - विशेष प्रयोजन कोष (Special Purpose Fund - SPF):**

- ANRF के अंतर्गत स्थापित यह कोष मुख्य निधि संरक्षक के रूप में कार्य करेगा।
- यह कोष दूसरे स्तर के निधि प्रबंधकों को पूंजी आवंटित करेगा।

**Tier 2 - द्वितीय स्तरीय निधि प्रबंधक (2nd-Level Fund Managers):**

- ये प्रबंधक निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स को कम या शून्य ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण देंगे।
- इससे जोखिम कम होगा और बड़ी संख्या में नवाचार परियोजनाएं आगे बढ़ सकेंगी।

**संस्थागत निगरानी:**

- ANRF की गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे।
- योजना सरकार और उद्योग के बीच साझा मॉडल के रूप में कार्य करेगी, जिससे नवाचार को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी जा सके।

**योजना का महत्व:**

- विशेष रूप से स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए जोखिम पूंजी (risk capital) को अनलॉक करना।
- भारत को एक वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करना।
- तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करना; मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशनों को समर्थन देना।
- **National Deep-Tech Strategy** और **विजन 2047** के तहत भारत की दीर्घकालिक तकनीकी आकांक्षाओं को साकार करना

**ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025: सबसे ज्यादा बिलियन डॉलर वाले स्टार्टअप वाले शीर्ष 10 देश**

**हरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025**, जो हरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया गया है, वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है। इस वर्ष, दुनिया भर में ऐसे निजी स्टार्टअप्स की कुल संख्या 1,523 तक पहुँच गई है जिनका मूल्यांकन \$1 बिलियन से अधिक है, जिन्हें कहा जाता है। इन कंपनियों का "यूनिकॉर्न" संयुक्त मूल्य \$5.6 ट्रिलियन है, जो वैश्विक नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में सबसे आगे खड़ी हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स अब वैश्विक अर्थव्यवस्था और तकनीकी प्रगति के प्रमुख वाहक बन चुके हैं।

**यूनिकॉर्न्स की वैश्विक वृद्धि**

2019 से अब तक, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वाले देशों की संख्या में 120% की वृद्धि हुई है, और अब ये आंकड़ा 52 देशों तक पहुँच चुका है। इसी तरह, यूनिकॉर्न अब 307 शहरों में फैले हुए हैं, जो भौगोलिक विविधता में साल-साल-दर-दर 160% की वृद्धि को दर्शाता है। यह प्रवृत्ति इस बात का प्रमाण है कि स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र अब पारंपरिक तकनीकी केंद्रों से आगे निकलकर वैश्विक स्तर पर विस्तृत हो चुका है।

**2025 में यूनिकॉर्न की संख्या के आधार पर शीर्ष 10 देश**

नीचे दी गई तालिका में उन 10 देशों की जानकारी दी गई है जिनमें 2025 में सबसे अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, साथ ही उन प्रमुख शहरों का उल्लेख है जहाँ यूनिकॉर्न गतिविधि सबसे ज्यादा देखी गई:

रैंक	देश	कुल यूनिकॉर्न	प्रमुख शहर (वैश्विक शहर रैंक के साथ)
1	संयुक्त राज्य अमेरिका	758	सैन फ्रांसिस्को (1), न्यूयॉर्क (2), बोस्टन (10), ऑस्टिन (14)
2	चीन	343	बीजिंग (3), शंघाई (4), शेनझेन (6), ग्वांगझोऊ (11)
3	भारत	64	बैंगलुरु (7), मुंबई (22), गुरुग्राम (27)
4	यूनाइटेड किंगडम	61	लंदन (5)
5	जर्मनी	36	बर्लिन (13)
6	फ्रांस	30	पेरिस (8)
7	कनाडा	28	टोरंटो (24)
8	इज़राइल	20	तेल अवीव (24)
9	दक्षिण कोरिया	18	सियोल (17)
9	सिंगापुर	18	सिंगापुर (14)

**देशवार प्रमुख विशेषताएँ**

**संयुक्त राज्य अमेरिका**

संयुक्त राज्य अमेरिका 758 यूनिकॉर्न के साथ दुनिया में सबसे आगे है, जो वैश्विक कुल का लगभग आधा है। पिछले वर्ष इसने 55 नए यूनिकॉर्न जोड़े। दुनिया के 10 सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न में से 6 अमेरिका में स्थित हैं। सैन फ्रांसिस्को 199 यूनिकॉर्न के साथ "विश्व की यूनिकॉर्न राजधानी" बना हुआ है, इसके बाद न्यूयॉर्क (142 यूनिकॉर्न) है।

**चीन**

चीन दूसरे स्थान पर है, जिसके पास 343 यूनिकॉर्न हैं, जो बीजिंग, शंघाई और शेनझेन जैसे तकनीकी केंद्रों में केंद्रित हैं।

प्रमुख चीनी यूनिकॉर्न में शामिल हैं: **ByteDance, Ant Group, और Shein।**

**भारत**

भारत 64 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर है। प्रमुख शहर: **बैंगलुरु, मुंबई, और गुरुग्राम।**

विकास के प्रमुख क्षेत्र: **फिनटेक, गेमिंग, और एडटेक।**

भारत के प्रमुख यूनिकॉर्न:

- **Zerodha** - \$8.2 बिलियन
- **Dream11** - \$8 बिलियन
- **Razorpay** - \$7.5 बिलियन

**यूनाइटेड किंगडम**

यूके 61 यूनिकॉर्न के साथ चौथे स्थान पर है, जिनमें से लगभग सभी लंदन में केंद्रित हैं (वैश्विक रैंक) 5वां।

प्रमुख क्षेत्र: **फिनटेक, AI, और डिजिटल हेल्थ।**

**जर्मनी और फ्रांस**

जर्मनी और फ्रांस महाद्वीपीय यूरोप के प्रमुख यूनिकॉर्न केंद्र बन रहे हैं।

- जर्मनी के **बर्लिन** में देश के सभी 36 यूनिकॉर्न हैं।
- फ्रांस के **पेरिस** में सभी 30 यूनिकॉर्न हैं।
- यूरोप वैश्विक नवाचार का एक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र बनता जा रहा है।

**कनाडा**

कनाडा 28 यूनिकॉर्न के साथ सातवें स्थान पर है। प्रमुख क्षेत्र: **क्लीन टेक, AI, और एंटरप्राइज़ सॉफ्टवेयर।**

**टोरंटो** देश का प्रमुख यूनिकॉर्न शहर है।

**इज़राइल**

20 यूनिकॉर्न के साथ इज़राइल की उपस्थिति मजबूत बनी हुई है, हालांकि इस वर्ष इसकी रैंकिंग में एक स्थान की गिरावट आई।

तेल अवीव मुख्य केंद्र है। प्रमुख क्षेत्र: **साइबर सुरक्षा, हेल्थटेक, और एग्रीटेक।**

**दक्षिण कोरिया और सिंगापुर**

दोनों देशों के पास **18-18 यूनिकॉर्न** हैं और ये **नौवें स्थान पर** हैं।

- दक्षिण कोरिया के यूनिकॉर्न मुख्य रूप से **सियोल** में केंद्रित हैं।
- सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया का उभरता हुआ स्टार्टअप हब बना हुआ है।

शीर्ष शहर

रैंक	शहर	यूनिकॉर्न की संख्या
1	सैन फ्रांसिस्को	199
2	न्यूयॉर्क	142
3	बीजिंग	91
4	शंघाई	69
5	लंदन	55
6	शेनझेन	46
7	बेंगलुरु	36
8	पेरिस	32
9	पालो अल्टो	30
10	बोस्टन	27

मुख्य अंतर्दृष्टियाँ

- संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन मिलकर दुनिया के 72% से अधिक यूनिकॉर्न की मेजबानी करते हैं।
- भारत की तीसरी रैंक वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।
- यूरोप (यूके, जर्मनी, फ्रांस धीरे यूनिकॉर्न की संख्या में वृद्धि कर-धीरे ( रहा है।
- सिंगापुर का उदय यह दर्शाता है कि दक्षिण पूर्व एशिया नवाचार-अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन रहा है।
- यूनिकॉर्न अब पारंपरिक टेक सेक्टर से आगे बढ़कर फिनटेक, हेल्थकेयर, ग्रीन एनर्जी, शिक्षा, और गेमिंग क्षेत्रों में भी सक्रिय हो गए हैं।

**संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025: शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश**

संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2015 में अपनाए गए सतत विकास लक्ष्य (SDGs) का उद्देश्य 2030 तक एक अधिक न्यायसंगत, हरित और समावेशी विश्व का निर्माण करना था। लेकिन हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क (SDSN) द्वारा प्रकाशित 2025 सतत विकास रिपोर्ट (SDR) की तस्वीर चिंताजनक है। रिपोर्ट के अनुसार, 17 में से कोई भी सतत विकास लक्ष्य 2030 तक पूरी तरह हासिल होने की राह पर नहीं है, और केवल 17% लक्ष्य ही अपेक्षा के अनुरूप प्रगति कर रहे हैं। हालाँकि बुनियादी सेवाओं, आधारभूत संरचना और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में कुछ हद तक प्रगति हुई है, लेकिन मीडिया स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार की धारणा, पोषण और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर गिरावट दर्ज की गई है।

वैश्विक रैंकिंगदो दुनियाओं की कहानी :

**SDG इंडेक्स 2025 में शीर्ष 10 देश**

यूरोप, विशेषकर नॉर्डिक देश, सतत विकास की दिशा में वैश्विक प्रयासों में लगातार अग्रणी बने हुए हैं। फिनलैंड ने एक बार फिर शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जिसके बाद स्वीडन और डेनमार्क क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

रैंक	देश	स्कोर (2025)
1	फिनलैंड	87.0
2	स्वीडन	85.7
3	डेनमार्क	85.3
4	जर्मनी	83.7
5	फ्रांस	83.1
6	ऑस्ट्रिया	83.0
7	नॉर्वे	82.7
8	क्रोएशिया	82.4
9	पोलैंड	82.1
10	चेकिया (चेक गणराज्य)	81.9

ये देश गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, जलवायु कार्रवाई, और शांति एवं न्याय जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर, SDG इंडेक्स 2025 में निचले पायदान पर वे देश हैं जो सशस्त्र संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता, और आर्थिक संकट जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन स्थितियों के चलते सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में उनकी प्रगति अत्यंत धीमी रही है।

रैंक	देश	स्कोर (2025)
167	दक्षिण सूडान	41.6
166	मध्य अफ्रीकी गणराज्य	45.2
165	चाड	46.0
164	सोमालिया	46.1
163	यमन गणराज्य	47.7
162	कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य	48.2
161	सूडान	49.1
160	अफ़गानिस्तान	49.1
159	नाइजर	50.3
158	मेडागास्कर	51.0

ये देश अक्सर सीमित राजकोपीय संसाधनों, प्राकृतिक आपदाओं, हिंसा और बुनियादी सेवाओं की कमी जैसी समस्याओं से जूझते हैं, जो सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की दिशा में उनकी प्रगति को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं।

**भारत की SDG रैंकिंग में ऐतिहासिक प्रगति**

**भारत पहली बार टॉप 100 में शामिल**

2025 के SDG इंडेक्स में भारत ने 99वाँ स्थान हासिल किया है, जिसका स्कोर 67.0 रहा। यह अब तक की भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इससे पहले भारत की स्थिति इस प्रकार रही थी:

- 2024: 109वाँ स्थान
- 2023: 112वाँ स्थान
- 2022: 121वाँ स्थान
- 2021: 120वाँ स्थान

भारत की यह लगातार सुधार होती रैंकिंग यह दर्शाती है कि देश ने सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में साफसफाई, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल सार्वजनिक ढाँचे और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है।

### क्षेत्रीय तुलना में भारत की स्थिति

हालाँकि भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 100 देशों में प्रवेश कर चुका है, फिर भी दक्षिण एशिया के कई पड़ोसी देशों की तुलना में यह अभी भी पीछे है। यह दर्शाता है कि भारत ने प्रगति तो की है, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

देश	रैंक (2025)	स्कोर
मालदीव	53	उपलब्ध नहीं
भूटान	74	70.5
नेपाल	85	68.6
भारत	99	67.0
श्रीलंका	93	उपलब्ध नहीं
बांग्लादेश	114	उपलब्ध नहीं
पाकिस्तान	140	उपलब्ध नहीं

भारत ने भले ही बांग्लादेश और पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन यह अब भी भूटान, नेपाल और श्रीलंका से पीछे है, जो यह संकेत देता है कि क्षेत्रीय सहयोग और साझा सीखने की पर्याप्त गुंजाइश अब भी मौजूद है।

### एशिया और ग्लोबल साउथ से मुख्य झलकियाँ

#### दक्षिण और दक्षिणपूर्व एशिया में उल्लेखनीय प्रगति-

2015 के बाद से एशिया के कई देशों ने स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं:

देश	स्कोर में सुधार
नेपाल	+11.1 अंक
कंबोडिया	+10.0 अंक
फिलीपींस	+8.6 अंक

इन देशों की प्रगति यह दर्शाती है कि यदि नीतियाँ लक्षित हों और उन्हें अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त हो, तो कम आय वाले देश भी सतत विकास लक्ष्यों में तेज़ी से सुधार कर सकते हैं।



### चीन और अमेरिकाजुला प्रदर्शन-मिला :

देश	रैंक (2025)	स्कोर
चीन	49	74.4
संयुक्त राज्य अमेरिका	44	75.2

दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ होने के बावजूद, ये दोनों देश शीर्ष 40 में नहीं आ सके।

इनकी रैंकिंग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं:

- असमानता (Inequality)
- पर्यावरणीय टिकाऊपन की कमी
- स्वास्थ्य परिणामों में असंतुलन

### असमानता (Inequality) 2025 में वैश्विक चुनौतियाँ

हालाँकि कुछ क्षेत्रों में प्रगति हुई है, फिर भी वैश्विक स्तर पर SDGs की दिशा में प्रगति पटरी से उतरी हुई है।

### 2025 सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार:

- केवल 17% लक्ष्य ही समय पर प्रगति कर रहे हैं
- मोटापा (Obesity), भ्रष्टाचार और मीडिया पर अंकुश में वृद्धि हो रही है
- पर्यावरणीय क्षरण (विशेषकर नाइट्रोजन प्रबंधन) तेज़ी से बिगड़ रहा है
- लैंगिक असमानता और आय विषमता विकसित और विकासशील देशों दोनों में जारी है

### समाधान की दिशा में सुझाव:

रिपोर्ट इस बात पर बल देती है कि 2030 तक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है:

- वैश्विक सहयोग में वृद्धि
- वित्तीय निवेश को बढ़ावा
- डेटाआधारित नीति निर्माण-
- स्थानीय और वैश्विक रणनीति में तालमेल

### PM मोदी को घाना में मिला 'ऑर्डर ऑफ द स्टार' सम्मान

एक ऐतिहासिक कूटनीतिक दिशा में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, "ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना" से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा द्वारा दिया गया यह सम्मान पीएम मोदी की वैश्विक राजनेता, दक्षिण-दक्षिण सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता और भारत-घाना द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में उनकी भूमिका को मान्यता देता है। भारतीय प्रधानमंत्री ने यह पुरस्कार भारत के युवाओं, इसकी विविध सांस्कृतिक विरासत और दोनों देशों के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित किया।

### खबरों में क्यों?

पीएम मोदी को घाना का शीर्ष नागरिक सम्मान 3 जुलाई, 2025 को घाना की अपनी पहली राजकीय यात्रा के दौरान मिला। यह सम्मान उनके नेतृत्व का जश्न मनाता है और भारत और घाना के बीच कूटनीतिक जुड़ाव को मजबूत करता है, खासकर व्यापार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में।

**सम्मान के बारे में**

- **पुरस्कार का नाम:** घाना के स्टार ऑफिसर का सम्मान
- **द्वारा प्रदान किया गया:** राष्ट्रपति **जॉन ड्रामानी महामा**
- **कारण:** पीएम मोदी के विशिष्ट वैश्विक नेतृत्व, कूटनीतिक पहुंच और दक्षिणदक्षिण सहयोग बनाने के प्रयासों के सम्मान में।-

**प्रमुख समझौते और घोषणाएँ**

अकरा में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए कई रणनीतिक पहलों का अनावरण किया।

**शिक्षा और युवा विकास**

- घाना के छात्रों के लिए ITEC और ICCR छात्रवृत्ति को दोगुना करना
- युवाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए घाना में एक कौशल विकास केंद्र की स्थापना

**कृषि और खाद्य सुरक्षा**

- भारत ने घाना के 'फ्रीड घाना' कार्यक्रम को समर्थन देने का वादा किया, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञता और संसाधन साझा किए

**स्वास्थ्य सेवा**

- घाना में जन औषधि केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव, सस्ती जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराना
- टीका उत्पादन सहयोग पर चर्चा

**डिजिटल और वित्तीय एकीकरण**

- भारत घाना को अपना भारत यूपीआई डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा, जिससे वित्तीय समावेशन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में वृद्धि होगी

**व्यापार संबंध**

- नए व्यापार और निवेश के अवसरों के माध्यम से अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा को दोगुना करने के लिए समझौता

**यात्रा का महत्व**

- 30 से अधिक वर्षों में घाना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री।
- अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण के लिए भारत की रणनीतिक पहुंच को मजबूत करता है।
- जवाहरलाल नेहरू और नेहरू द्वारा शुरू किए गए ऐतिहासिक संबंधों को आगे बढ़ाता है क्वामे नक्रमा।
- साझा लोकतांत्रिक आदर्शों और आपसी विकास लक्ष्यों के आधार पर सहयोग को गहरा करता है।

**पीएम मोदी को मिला त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 जुलाई 2025 को त्रिनिदाद और टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें उनकी वैश्विक नेतृत्व क्षमता, भारतीय प्रवासी समुदाय से गहरे जुड़ाव और कोविड-19 महामारी के दौरान मानवीय प्रयासों के लिए दिया गया। बता दें कि पीएम मोदी फिलहाल पांच देशों के दौर पर हैं और त्रिनिदाद और टोबैगो की यह दो दिन

की यात्रा उनका दूसरा पड़ाव है। वहीं सम्मान मिलने के बाद उन्होंने कहा, 'त्रिनिदाद एंड टोबैगो के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होकर मैं गौरवान्वित हूँ। मैं यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों की ओर से स्वीकार करता हूँ।'

**ऐतिहासिक पहली यात्रा**

यह प्रधानमंत्री मोदी की त्रिनिदाद और टोबैगो की पहली आधिकारिक यात्रा है। साथ ही, यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 1999 के बाद पहली त्रिनिदाद यात्रा भी है। यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की पाँच देशों की यात्रा का हिस्सा है, जो भारत और द्वीपीय राष्ट्र के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को नई ऊँचाई पर ले जाने का संकेत देती है।

**सम्मान मिलने का कारण**

"ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो" प्रधानमंत्री मोदी को उनके वैश्विक नेतृत्व, प्रवासी भारतीय समुदाय के लिए कार्य, और कोविड-19 महामारी के दौरान सहायता के लिए प्रदान किया गया। त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसादबिसेसर- ने यह सम्मान देने की घोषणा की और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा दोनों देशों के बीच गर्व और जुड़ाव का प्रतीक है।

**पीएम मोदी की प्रतिक्रिया और सांस्कृतिक भेंट**

सम्मान प्राप्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह यह पुरस्कार 140 करोड़ भारतीयों की ओर से स्वीकार कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने त्रिनिदाद की प्रधानमंत्री को महाकुंभ का पवित्र जल और राम मंदिर की एक प्रतिकृति भेंट की। यह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक माना गया।

**इससे पहले घाना का दौरा**

त्रिनिदाद यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने घाना का दौरा किया था, जहाँ उन्हें देश के एक और प्रतिष्ठित सम्मान "ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना" से नवाज़ा गया। भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, यह सम्मान उन्हें वैश्विक सहयोग में योगदान और मजबूत नेतृत्व के लिए दिया गया।

**भारत और त्रिनिदाद एवं टोबैगो ने संबंधों को बढ़ावा देने के लिए छह नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए**

भारत और त्रिनिदाद एवं टोबैगो ने 4 जुलाई 2025 को पोर्ट ऑफ स्पेन में छह महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के बीच साझेदारी को कई क्षेत्रों में मजबूती मिलेगी। इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, चिकित्सा, संस्कृति और खेल शामिल हैं। ये समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की त्रिनिदाद एवं टोबैगो यात्रा के दौरान हुए, जो दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

**25 वर्षों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा**

यह 1999 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की त्रिनिदाद एवं टोबैगो की पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसादबिसेसर से मुलाकात- की और सहयोग को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बातचीत की। दोनों नेताओं ने कृषि, शिक्षा, डिजिटल भुगतान और स्वास्थ्य सेवाओं में भविष्य की साझेदारी पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए।

इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने आपसी गर्मजोशी और सम्मान का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री बिसेसर ने इसे एक बताया "ऐतिहासिक क्षण" जो दोनों देशों की मित्रता को नई ऊर्जा देगा।

### छह समझौतों पर हस्ताक्षर

भारत और त्रिनिदाद एवं टोबैगो के बीच छह समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देंगे:

- औषधि मानकों में सहयोग
- त्वरित विकास परियोजनाएं
- सांस्कृतिक आदानप्रदान-
- खेलों का प्रचारप्रसार-
- राजनयिक प्रशिक्षण
- आधिकारिक दस्तावेजों और शोध साझा करना

इन समझौतों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना, सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना और जन जन के बीच संबंधों को मजबूत-करना है।

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी घोषणा की कि अब त्रिनिदाद एवं टोबैगो में रहने वाले भारतीय मूल के लोग, भले ही वे छठी पीढ़ी के हों, भारत के ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह निर्णय प्रवासी भारतीयों को भारत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

### राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात

प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद एवं टोबैगो की राष्ट्रपति **क्रिस्टीन कार्ला कांगालू** से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति कांगालू को हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोनों नेताओं की बैठक सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक रही। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति की जनसेवा और नेतृत्व की प्रशंसा की।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत और त्रिनिदाद एवं टोबैगो "ग्लोबल साउथ" यानी वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मिलकर कार्य करेंगे, जिनमें जलवायु संकट और निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रमुख हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने पहलुगाम आतंकी हमले के बाद भारत को समर्थन देने के लिए त्रिनिदाद एवं टोबैगो का आभार भी व्यक्त किया और कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं।



### National Affairs

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक नया नियम पेश किया है जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुछ विशेष हिस्सों जैसे सुरंगों (टनल), पुलों, फ्लाईओवर और एलिवेटेड सड़कों पर टोल शुल्क 50% तक कम हो जाएगा। इस कदम का उद्देश्य यात्रा को सस्ता बनाना और लोगों को राजमार्गों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है। ([Click here to read article](#))
- भारत यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्मार्ट योजना पर काम कर रहा है कि देश कभी भी तेल की कमी से न जूझे, चाहे किसी भी आपात स्थिति का सामना क्यों न करना पड़े। सरकार तीन नए रणनीतिक तेल भंडार बनाने की योजना बना रही है। ये ऐसे बड़े भंडारण क्षेत्र होंगे, जहां देश भविष्य की जरूरतों के लिए कच्चा तेल सुरक्षित रख सकेगा। ([Click here to read article](#))
- हालांकि, लंबे समय तक जीने का मतलब हमेशा स्वस्थ रहना नहीं होता। पार्किंसंस और डिमेंशिया जैसी उम्र से जुड़ी बीमारियों के बढ़ते मामलों के साथ, यह समझने की जरूरत बढ़ रही है कि भारतीय कैसे बूढ़े होते हैं – सिर्फ सालों के हिसाब से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के हिसाब से भी। ([Click here to read article](#))
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में एक ऑडिटोरियम, शैक्षणिक ब्लॉक और पंचकर्म केंद्र सहित प्रमुख सुविधाओं का उद्घाटन किया और एक नए बालिका छात्रावास की आधारशिला रखी – जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। ([Click here to read article](#))
- स्थायी खनन और सामुदायिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कोयला मंत्रालय रिक्लेम फ्रेमवर्क लॉन्च करने जा रहा है – समावेशी खदान बंद करने और पुनः उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक संरचित मार्गदर्शिका। यह पहल सामुदायिक भागीदारी, लैंगिक समावेशिता और कमजोर समूहों की भागीदारी पर जोर देती है, जिसका उद्देश्य खनन के बाद के बदलाव को न्यायसंगत, पारदर्शी और स्थानीय रूप से संरेखित बनाना है। ([Click here to read article](#))
- भारत की अग्रणी समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले को सम्मानित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (National Institute of Public Cooperation and Child Development) का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान (Savitribai Phule National Institute of Women and Child Development) कर दिया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा घोषित यह नाम परिवर्तन देश भर में महिलाओं और बाल कल्याण के लिए समावेशी, क्षेत्र-विशिष्ट और मिशन-संचालित समर्थन के लिए सरकार की नई प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ([Click here to read article](#))

**States in the News**

- सी-डैक, सीडब्ल्यूसी और एनआरएससी द्वारा सहयोग से विकसित यह वेब-आधारित प्लेटफॉर्म गांव स्तर पर दो दिन का अग्रिम बाढ़ पूर्वानुमान प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्रों में तैयारी को बढ़ाना और बाढ़ के जोखिम को कम करना है। यह परियोजना राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (एनएसएम) का हिस्सा है, जो जलवायु चुनौतियों से निपटने में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तालमेल को प्रदर्शित करती है। [\(Click here to read article\)](#)
- रेलवे सेवाओं में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 जुलाई, 2025 को 'रेलवन' मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया। एक व्यापक, वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित, ऐप यात्रियों को टिकट बुकिंग, पीएनआर पूछताछ, यात्रा योजना, भोजन बुकिंग और माल हुलाई पूछताछ जैसी सेवाओं तक एकीकृत पहुंच प्रदान करता है, जिससे लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा और डिजिटल अनुभव बढ़ जाता है। [\(Click here to read article\)](#)
- भारत के पंजाब राज्य के फाजिल्का जिले में स्थित भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा — श्री नानक निवास — श्रद्धा और सेवा (सेवा भाव) का एक अनुपम उदाहरण बनकर उभरा है। यह गुरुद्वारा फिनलैंड से आयातित देवदार लकड़ी से पूरी तरह से निर्मित है और इसे पुलिस लाइन परिसर के अंदर स्थापित किया गया है। यह धार्मिक स्थल न केवल आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि स्थायी वास्तुकला और सार्वजनिक सेवा के समन्वय का भी प्रेरणादायक उदाहरण है। इस अनूठे गुरुद्वारे की परिकल्पना एसएसपी भूपिंदर सिंह सिद्धू ने की थी, जिनकी व्यक्तिगत श्रद्धा ने इसे 2023 में साकार किया। [\(Click here to read article\)](#)
- भारतीय रेलवे ने यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और आरक्षण प्रणाली को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक सुधार योजना की घोषणा की है। इन सुधारों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे टिकट बुकिंग से लेकर यात्रा तक की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बन सके। [\(Click here to read article\)](#)
- भारत के चुनाव आयोग ने 345 गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों (RUPPs) को अपनी लिस्ट से हटाने का फैसला किया है। ये वे दल हैं जो पिछले 6 सालों में एक भी चुनाव नहीं लड़े और इनके पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं मिला। चुनाव आयोग ने बताया कि देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले इन 345 दलों ने रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बने रहने की अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं किया। आयोग के पास वर्तमान में 2800 से ज्यादा RUPPs रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इनमें से कई दल न तो चुनाव लड़ रहे हैं और न ही अपनी मौजूदगी साबित कर पा रहे हैं। [\(Click here to read article\)](#)
- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 29 जून 2025 को "कृषि भूमि में पेड़ों की कटाई के लिए मॉडल नियम" जारी किए। यह पहल सतत कृषि, आजीविका संवर्धन, और आग्रोफॉरेस्ट्री (Agroforestry) को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही मंत्रालय ने आगामी नेशनल टिंबर मैनेजमेंट सिस्टम (NTMS) पोर्टल की भी घोषणा की, जो वृक्ष कटाई की मंजूरी प्रक्रिया को डिजिटली सरल बनाएगा। [\(Click here to read article\)](#)

- ओडिशा के प्रसिद्ध तीर्थ और पर्यटन नगर पुरी को अब नगर निगम (Municipal Corporation) का दर्जा दिया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 5 जुलाई 2025 को बहुदा यात्रा से पहले की। इस फैसले का उद्देश्य उस शहर की आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। [\(Click here to read article\)](#)
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, गुजरात आधिकारिक तौर पर एक करोड़ पंजीकृत शेयर बाजार निवेशकों का मील का पत्थर पार करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। यह उपलब्धि गुजरात को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के साथ इस मील के पत्थर तक पहुंचने वाले एकमात्र अन्य राज्यों में से एक बनाती है। [\(Click here to read article\)](#)
- जम्मू और कश्मीर (J&K) में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बड़े कदम के रूप में, भारत सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के दूसरे चरण के तहत एक एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करने के लिए ₹100 करोड़ के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह ने जम्मू में 50,000 लीटर के यूएचटी दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी वर्चुअल उद्घाटन किया, जिससे क्षेत्र में पशुधन और जलीय कृषि विकास के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई। [\(Click here to read article\)](#)
- भारत सरकार ने तमिलनाडु के विरुधुनगर में ₹1,900 करोड़ के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जो वैश्विक कपड़ा उद्योग में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 1,052 एकड़ में फैले इस मेगा पार्क में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) ट्रीटमेंट, 10,000 बिस्तरों वाला डॉरमेट्री और 1.3 मिलियन वर्ग फीट से ज्यादा रेडी-टू-यूज औद्योगिक स्थान सहित अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा होगा। तकनीकी वस्त्र और टिकाऊ परिधान निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, इस पार्क से 2026 तक ₹10,000 करोड़ का निवेश आने और एक लाख से अधिक नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। [\(Click here to read article\)](#)
- तमिलनाडु में क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के कदम में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2025 को परमकुडी और रामनाथपुरम के बीच चार लेन के राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी। यह परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग-87 (NH-87) का हिस्सा है, जिसे ₹1,853 करोड़ की पूंजी लागत से हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM) के तहत विकसित किया जाएगा। इस रणनीतिक उन्नयन से यातायात की भीड़ कम होने, सुरक्षा में सुधार होने और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद है। [\(Click here to read article\)](#)
- युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने और सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, बिहार मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2025 को कई कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें इंटरशिप सहायता के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, वरिष्ठ कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना और सीतामढ़ी में प्रतिष्ठित पुनौरा धाम मंदिर के लिए 882 करोड़ रुपये की विकास योजना शामिल है। ये योजनाएं विधानसभा चुनावों से पहले रोजगार, संस्कृति और पर्यटन को संबोधित करने के सरकार के प्रयासों को दर्शाती हैं। [\(Click here to read article\)](#)

- पुरी ओडिशा का छठा नगर निगम बन जाएगा, जैसा कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 5 जुलाई, 2025 को बहुदा यात्रा से पहले घोषणा की थी। इस निर्णय का उद्देश्य शहर में बेहतर सेवाएँ प्रदान करना है, जहाँ हर साल लाखों आगंतुक आते हैं। पुरी शहर के आस-पास के क्षेत्रों को निगम में जोड़ा जाएगा, और सरकार ने ओडिशा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जगन्नाथ संग्रहालय, पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र की भी योजना बनाई है। यह कदम 2036 तक पुरी को एक प्रमुख पर्यटक और आध्यात्मिक केंद्र बनाने के राज्य के दृष्टिकोण का समर्थन करता है। ([Click here to read article](#))

### International Affairs

- यूरोपीय संघ (EU) ने 2 जुलाई 2025 को अपने लंबे समय से प्रतीक्षित जलवायु योजना की घोषणा की, जिसके तहत 2040 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर की तुलना में 90% तक घटाने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की ईयू की व्यापक प्रतिबद्धता का हिस्सा है। हालांकि, सभी सदस्य देशों का समर्थन सुनिश्चित करने के लिए इस योजना में कुछ लचीलापन जोड़ा गया है, जिससे विभिन्न देशों में बहस छिड़ गई है। ([Click here to read article](#))
- रूस ने अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है, और 2021 के बाद ऐसा करने वाला वह पहला देश बन गया है। यह ऐतिहासिक कदम अफ़गानिस्तान के साथ वैश्विक राजनयिक संबंधों को नया आकार दे सकता है और व्यापक अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव के द्वार खोल सकता है। ([Click here to read article](#))
- पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का अध्यक्ष बन गया है और वो इस पूरे महीने ही अध्यक्ष रहेगा। हालांकि उसे किसी वोटिंग के जरिए ये अध्यक्षता नहीं मिली, बल्कि रोटेशन नंबर आने से ये मौका मिला है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद पूरे महीने परिषद का नेतृत्व करेंगे। पाकिस्तान इसी साल जनवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया था। परिषद की अध्यक्षता इसके 15 सदस्य देशों के बीच बदलती रहती है। इस परिषद में 5 स्थायी सदस्य के अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ([Click here to read article](#))
- औद्योगिक सहयोग बढ़ाने और संधारणीय विनिर्माण को आगे बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में, भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने हरित इस्पात और उच्च श्रेणी के एल्युमीनियम के उत्पादन में सहयोग करने के लिए चर्चा शुरू की है। केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने स्वच्छ ऊर्जा-संचालित धातु विज्ञान, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और दीर्घकालिक संसाधन सुरक्षा में तालमेल का पता लगाने के लिए भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) ढांचे के तहत यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री महामहिम अब्दुल्ला बिन तौक अल मारी से मुलाकात की। ([Click here to read article](#))

- एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव में, ग्रुप ऑफ सेवन (G7) देशों ने अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वैश्विक न्यूनतम कर ढांचे से छूट देने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे उन्हें एक विशेष "साइड-बाय-साइड" कराधान समाधान की पेशकश की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन द्वारा आगे बढ़ाई गई यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करेगी कि अमेरिकी निगमों पर घरेलू और विदेशी दोनों तरह के मुनाफ़े पर केवल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कर लगाया जाए, जो संभवतः 2021 से OECD ढांचे के तहत बातचीत की गई वैश्विक कर संरचना को नया रूप दे सकता है। ([Click here to read article](#))
- भारत ने बांग्लादेश से भूमि मार्ग से कुछ जूट उत्पादों और बुने हुए कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि इसकी अनुमति केवल न्हावा शेवा बंदरगाह के माध्यम से दी गई है। 17 मई को भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों जैसी कुछ वस्तुओं के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगा दिया था। इन प्रतिबंधों के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में जूट उत्पाद, एकल सन यार्न, जूट का एकल यार्न, बुने हुए कपड़े या फ्लेक्स तथा जूट के बिना साफ किए बुने हुए कपड़े शामिल हैं। ([Click here to read article](#))
- यूरोपीय संघ (ईयू) ने 2 जुलाई, 2025 को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 90% की कटौती करने के लिए 2040 के अपने जलवायु लक्ष्य को साझा किया, जिसका लक्ष्य 2050 तक कार्बन तटस्थता हासिल करना है। व्यापक समर्थन प्राप्त करने के लिए, योजना 2036 से 3% तक अंतर्राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट का उपयोग करने की अनुमति देती है। इसने जलवायु समूहों के बीच इस प्रयास के कमजोर होने की चिंता जताई है। वोपके होकेस्ट्रा और उर्सुला वॉन डेर लेयेन जैसे प्रमुख यूरोपीय संघ के नेताओं ने इस योजना का महत्वाकांक्षी लेकिन लचीला बताते हुए बचाव किया। अंतिम निर्णय जुलाई में चर्चा और सितंबर में मतदान के बाद आया, उम्मीद है कि इसे ब्राजील में COP30 से पहले पारित कर दिया जाएगा। ([Click here to read article](#))

### Agreements/MoUs Signed

- भारत-श्रीलंका सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए कोलंबो स्थित जनरल सर जॉन कोटेलावाला रक्षा विश्वविद्यालय (KDU) ने हिंदी भाषा सीखने का कार्यक्रम शुरू किया है। यह पहल श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग की सांस्कृतिक शाखा स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र (SVCC) के सहयोग से की गई है। ([Click here to read article](#))

### Banking/Economy/Business News

- प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपने 25 वर्षों से चल रहे ऑपरेशन को 3 जुलाई 2025 को बंद कर दिया। यह कदम कंपनी की वैश्विक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वह अपने कर्मचारियों की संख्या घटा रही है और क्लाउड-आधारित सेवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। इस फैसले को कई विशेषज्ञ पाकिस्तान के व्यापारिक माहौल के लिए चिंताजनक संकेत मान रहे हैं। ([Click here to read article](#))

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने जून 2025 में कुल 229.33 करोड़ आधार ऑथेंटिकेशन लेनदेन की सूचना दी, जो विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल पहचान सत्यापन के लिए आधार पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है। यह आंकड़ा जून 2024 में दर्ज किए गए लेनदेन की तुलना में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जो देश के डिजिटल परिवर्तन और आर्थिक गतिविधियों में आधार की बढ़ती भूमिका पर जोर देता है। ([Click here to read article](#))
- भारत के इस्पात क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में अपने पहले अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया है। यह कंपनी की वैश्विक विस्तार योजना में एक रणनीतिक कदम है और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी इस्पात निर्माता के रूप में विकसित होने की इसकी महत्वाकांक्षा को पुष्ट करता है। ([Click here to read article](#))
- भारत के रक्षा क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हुए रिलायंस डिफेंस (Reliance Defence)—जो रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी है—ने अमेरिका स्थित रक्षा ठेकेदार कोस्टल मैकेनिक्स इंक. (Coastal Mechanics Inc. - CMI) के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत महाराष्ट्र के नागपुर स्थित MIHAN (मल्टी-मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट) में एक अत्याधुनिक MRO (मैटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल) सुविधा की स्थापना की जाएगी। यह संयुक्त उपक्रम भारतीय सशस्त्र बलों और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए वायु और थल रक्षा प्लेटफार्मों के उन्नयन पर केंद्रित होगा, जो "आत्मनिर्भर भारत" अभियान के अनुरूप है। ([Click here to read article](#))
- अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने बताया कि कंपनी ने 15,000 मेगावाट (मेगावाट) की परिचालन क्षमता को पार कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो कि अब 15,539.9 मेगावाट तक पहुंच गई है। यह उपलब्धि भारत में अब तक की सबसे तेज और बड़ी क्षमता वृद्धि को दर्शाती है। भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ने कहा कि परिचालन पोर्टफोलियो में 11,005.5 मेगावाट सोलर, 1,977.8 मेगावाट विंड और 2,556.6 मेगावाट विंड-सोलर हाइब्रिड क्षमता शामिल है। ([Click here to read article](#))
- भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था, जिसे वर्ष 2017 में लागू किया गया था, ने राजस्व संग्रह के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में भारत का सकल GST संग्रह ₹22.08 लाख करोड़ तक पहुंच गया — जो अब तक का सर्वाधिक वार्षिक संग्रह है। यह उपलब्धि FY21 के ₹11.37 लाख करोड़ से दोगुनी वृद्धि को दर्शाती है। ([Click here to read article](#))
- भारत का वाणिज्यिक वाहन (CV) क्षेत्र वित्त वर्ष 2025-26 में धीरे-धीरे पुनरुद्धार की ओर बढ़ रहा है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्र में इस साल थोक विक्री में साल-दर-साल (Y-o-Y) 3-5% की वृद्धि की उम्मीद है। यह अनुमान पिछले वर्ष (FY25) में दर्ज की गई 1.2% गिरावट के बाद सामने आया है। इस सुधार का मुख्य कारण निर्माण एवं अवसंरचना गतिविधियों में तेजी और समग्र आर्थिक स्थिति में स्थिरता है। हालांकि, डीलरों के पास उच्च स्तर की इन्वेंट्री और कुछ CV वर्गों में कमजोर मांग अभी भी प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं। ([Click here to read article](#))
- कृषि और संबद्ध क्षेत्र से उत्पादन का सकल मूल्य (जीवीओ) वित्त वर्ष 2012 से वित्त वर्ष 2024 के दौरान स्थिर मूल्यों पर 54.6 प्रतिशत बढ़कर 29.49 लाख करोड़ रुपये हो गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने यह जानकारी दी। सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के तहत आने वाले एनएसओ ने 'कृषि व संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकीय रिपोर्ट (2011-12 से 2023-24)' का वार्षिक प्रकाशन जारी किया है। ([Click here to read article](#))
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा कि भारत का बाह्य यानी विदेशी ऋण मार्च 2025 के अंत तक 10 प्रतिशत बढ़कर 736.3 अरब डॉलर हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 668.8 अरब डॉलर था। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बाह्य ऋण एक साल पहले के 18.5 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 के अंत तक 19.1 प्रतिशत हो गया। आरबीआई ने कहा कि समीक्षाधीन वित्त वर्ष में मुद्रा बाजारों में कुछ उतार-चढ़ाव देखा गया, और रुपये तथा अन्य मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर के मूल्य में वृद्धि के कारण 'मूल्यांकन प्रभाव' 5.3 अरब डॉलर रहा। ([Click here to read article](#))
- भारत के बाह्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार दर्ज करते हुए, देश ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही (Q4 FY25) में \$13.5 बिलियन का चालू खाता अधिशेष (जो GDP का 1.3% है) दर्ज किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, यह पिछले वित्तीय तिमाही (Q3 FY25) में दर्ज \$11.3 बिलियन के घाटे से एक बड़ा मोड़ दर्शाता है। साथ ही, यह Q4 FY24 में दर्ज \$4.6 बिलियन के अधिशेष की तुलना में भी उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है। यह बदलाव भारत के सेवाओं के निर्यात, रेमिटेंस, और प्राथमिक आय में संतुलन की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है, जो देश की बाहरी स्थिरता को मज़बूत करता है। ([Click here to read article](#))
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 30 जून 2025 को सभी बैंकों को एक नया सिस्टम अपनाने का निर्देश दिया, जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर (FRI)। यह उपकरण दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है। यह टूल संदिग्ध मोबाइल नंबरों की रीयल-टाइम पहचान में मदद करता है, जिससे बैंकों को अपने ग्राहकों की सुरक्षा करने में आसानी होती है। ([Click here to read article](#))



- एसबीआई रिसर्च की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 297 अरब डॉलर का योगदान दिया, जो कि वैश्विक GDP वृद्धि का 6.7% है। इसमें से अकेले भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 44 अरब डॉलर यानी 1.1% वैश्विक वृद्धि में हिस्सेदारी निभाई। यह रिपोर्ट न केवल भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को दर्शाती है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि एसबीआई जैसी संस्थाएं भारत और वैश्विक दोनों स्तरों पर आर्थिक विकास को गति देने में अहम भूमिका निभा रही हैं। ([Click here to read article](#))
- संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के प्रमुख बैंक मशरिफ (Mashreq) को गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी (GIFT City) में शाखा खोलने के लिए इन-प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। यह भारत के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में प्रवेश करने वाला पहला यूईई-आधारित बैंक बन गया है। यह कदम भारत-UAE के बीच वित्तीय सहयोग को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ([Click here to read article](#))
- भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने दो नए कार्यालय खोले हैं। इन्हें ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर कहा जाता है। इनमें से एक कोलकाता में और दूसरा हैदराबाद में है। यह मंगलवार को हुआ और यह बैंक और उसके ग्राहकों के लिए गर्व का क्षण है। ([Click here to read article](#))
- साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ भारत की रक्षा को मजबूत करने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी प्रमुख वित्तीय संस्थानों को दूरसंचार विभाग (DoT) के नए विकसित वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (Financial Fraud Risk Indicator) को एकीकृत करने का निर्देश दिया है। यह पहल उच्च जोखिम वाले मोबाइल नंबरों को चिह्नित करके वास्तविक समय में खतरे का पता लगाने में सक्षम बनाती है, जिससे बैंकों को संदिग्ध डिजिटल लेनदेन को सक्रिय रूप से रोकने में मदद मिलती है। ([Click here to read article](#))
- दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से एक कदम उठाते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (CII) को 363 से बढ़ाकर 376 करने की घोषणा की है। इस सूचकांक का उपयोग मुद्रास्फीति के लिए परिसंपत्तियों के खरीद मूल्य को समायोजित करने के लिए किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि परिसंपत्तियों को बेचने पर केवल वास्तविक लाभ पर ही कर लगाया जाता है। हालांकि वित्त अधिनियम 2024 के तहत इंडेक्सेशन का दायरा कम कर दिया गया है, लेकिन अपडेट किया गया इंडेक्स अभी भी कुछ करदाताओं, खासकर 23 जुलाई, 2024 से पहले अर्जित संपत्ति रखने वालों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करता है। ([Click here to read article](#))
- एक प्रमुख व्यापार-समर्थक कदम के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) द्वारा लिए गए फ्लोटिंग रेट ऋणों पर पूर्व-भुगतान जुर्माना लगाने से रोक दिया है। 1 जनवरी, 2026 से लागू होने वाले इस निर्देश का उद्देश्य किराया ऋण तक पहुँच को बढ़ाना और छोटे व्यवसाय ऋण क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है। ([Click here to read article](#))
- देश की डिजिटल भुगतान क्रांति की रीढ़, भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) ने जून 2025 में ₹24.04 लाख करोड़ मूल्य के 18.40 बिलियन लेनदेन दर्ज किए। हालांकि यह मई के आंकड़ों से थोड़ी गिरावट दर्शाता है, लेकिन यह बड़े पैमाने पर UPI की परिपक्व और स्थिर वृद्धि को उजागर करता है, भले ही वार्षिक आंकड़े मजबूत विस्तार प्रदर्शित करना जारी रखते हैं। ([Click here to read article](#))
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की जून 2025 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report – FSR) के अनुसार, देश के बैंकिंग क्षेत्र में सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (Gross Non-Performing Assets – GNPA) मार्च 2025 में घटकर 2.3% पर आ गई है, जो कि पिछले कई दशकों का सबसे निचला स्तर है। सितंबर 2024 में यह आंकड़ा 2.6% था। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि मार्च 2027 तक GNPA फिर से बढ़कर 2.6% हो सकती है। ([Click here to read article](#))
- भारत की स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण यात्रा को एक नई गति देते हुए, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने वित्त वर्ष 2026-27 तक 40 लाख घरों में सोलर रूफटॉप स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषित किया है। यह पहल SBI की व्यापक सतत विकास दृष्टि का हिस्सा है, जो भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य के अनुरूप है। इस घोषणा को बैंक की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर सार्वजनिक किया गया, जो SBI की वित्तीय सेवा से लेकर राष्ट्रीय विकास तक की भूमिका को रेखांकित करता है। ([Click here to read article](#))
- कर्नाटक बैंक के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) श्रीकृष्णन हरि हर सरमा और कार्यकारी निदेशक शेखर राव ने इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक बैंक ने बयान में कहा, इसके अलावा कार्यकारी निदेशक (ईडी) शेखर राव ने मंगलुरु स्थानांतरित होने में असमर्थता और अन्य व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ दिया है। जुलाई 2025 से प्रभावी ये इस्तीफे बैंक के चल रहे परिवर्तन अभियान के बीच आए हैं। इसके जवाब में, निदेशक मंडल ने उपयुक्त उत्तराधिकारियों की नियुक्ति करने और निर्बाध नेतृत्व निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक खोज समिति का गठन किया है। ([Click here to read article](#))
- डिजिटल बैंकिंग को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आधार आधारित भुगतान प्रणाली (AEPS) से जुड़ी सेवाओं पर सख्त निगरानी के निर्देश जारी किए हैं। अब अंगूठा लगाकर बैंक से पैसे निकालने वाली प्रक्रिया में कड़े नियम लागू होंगे। RBI ने बैंकों से कहा है कि AEPS सेवाएं देने वाले ऑपरेटर्स को सिस्टम में जोड़ने से पहले उनकी अच्छी तरह से जांच-पड़ताल की जाए, ताकि फ्राँड और पहचान की चोरी जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। ([Click here to read article](#))

### Appointments/Resignations

- भारतीय खो-खो महासंघ ने देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खो-खो को बढ़ावा देने और विकसित करने के उद्देश्य से एक नई नेतृत्व टीम की शुरुआत की है। नव नियुक्त निकाय में पूरे भारत से अनुभवी व्यक्ति शामिल हैं, जो इस स्वदेशी खेल को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ([Click here to read article](#))
- सुनील कदम ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) में कार्यकारी निदेशक (ED) के रूप में महत्वपूर्ण नई भूमिका संभाली है। SEBI भारत में शेयर बाजार और वित्तीय लेन-देन को देखने वाला मुख्य संगठन है। SEBI में लगभग 30 वर्षों तक काम कर चुके कदम के लिए यह एक बड़ा कदम है। ([Click here to read article](#))
- भारतीय वायु सेना (IAF) के एक वरिष्ठ और अत्यधिक सम्मानित अधिकारी, एयर मार्शल एस. शिवकुमार ने अब नई दिल्ली स्थित वायु सेना मुख्यालय में वायु अधिकारी-इन-चार्ज प्रशासन (AOA) के रूप में पदभार संभाल लिया है। ([Click here to read article](#))
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) केशवन रामचंद्रन को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। आरबीआई ने उनकी नियुक्ति घोषणा एक जुलाई को की है। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पहले केशवन रामचंद्रन जोखिम निगरानी विभाग में प्रधान मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। केशवन रामचंद्रन ने अपने करियर के दौरान रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में भी काम किया। उन्होंने पांच साल से अधिक समय तक केनरा बैंक के बोर्ड में भारतीय रिजर्व बैंक के नामित सदस्य के रूप में और दो साल तक आईसीएआई के ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड में काम किया। ([Click here to read article](#))
- केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है। अब वह 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक अनुबंध के आधार पर इस पद पर बने रहेंगे। यह फैसला शनिवार को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet) ने लिया। रवि अग्रवाल भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के 1988 बैच के अधिकारी हैं। ([Click here to read article](#))
- केंद्र सरकार ने पंजाब कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी पराग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) का नया प्रमुख नियुक्त किया है। पराग, रवि सिन्हा की जगह लेंगे, जिनका मौजूदा कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। जैन 1 जुलाई 2025 को दो साल के निश्चित कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण करेंगे। ([Click here to read article](#))

### Defence News

- सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला बन गई हैं जिन्हें फाइटर पायलट प्रशिक्षण स्ट्रीम में शामिल किया गया है। यह ऐतिहासिक घोषणा 4 जुलाई 2025 को विशाखापत्तनम स्थित आईएनएस डेगा में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान की गई। यह भारतीय सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता (Gender Equality) की दिशा में एक बड़ा कदम है और महिलाओं के लिए रक्षा क्षेत्र में एक गौरवपूर्ण क्षण है। ([Click here to read article](#))

- भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, प्रोजेक्ट 17A के तहत दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरि 1 जुलाई, 2025 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। मुंबई में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDSL) द्वारा निर्मित, यह युद्धपोत उन्नत स्टील्थ क्षमताओं, आधुनिक हथियार प्रणालियों और तेज़ निर्माण समयसीमा को दर्शाता है। इसका शामिल होना भारत की आत्मनिर्भर नौसेना इंजीनियरिंग और ब्लू-वाटर ऑपरेशनल ताकत में एक छलांग है। ([Click here to read article](#))
- भारत ने 1 जुलाई, 2025 को रूस के कलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में INS तमाल (F71) को शामिल करके नौसेना में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। यह स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट भारतीय नौसेना के लिए विदेश में निर्मित अंतिम प्रमुख युद्धपोत है, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों के अनुरूप है। INS तमाल अब भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में शामिल हो जाएगा, जो ब्लू-वाटर ऑपरेशनल क्षमता को मजबूत करेगा और स्वदेशीकरण के एक नए युग का प्रदर्शन करेगा। ([Click here to read article](#))
- भारतीय नौसेना के एक प्रतिष्ठित अधिकारी रियर एडमिरल वी गणपति ने आधिकारिक तौर पर मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MILIT), पुणे की कमान संभाली है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत के सशस्त्र बल संयुक्तता के सिद्धांतों के अनुरूप गहन एकीकरण और तकनीकी उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं। अपनी समृद्ध परिचालन और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, रियर एडमिरल गणपति से उम्मीद की जाती है कि वे MILIT को तीनों सेनाओं की तकनीकी शिक्षा और नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएं। ([Click here to read article](#))

### Awards and Recognitions

- भारत के कलबुर्गी स्थित S.R.N. मेहता सीबीएसई स्कूल को NASA-NSS स्पेस सेटलमेंट डिज़ाइन प्रतियोगिता 2025 में कक्षा 8वीं श्रेणी के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 11 छात्रों की टीम द्वारा तैयार की गई इस परियोजना ने अपनी रचनात्मक सोच और सतत अंतरिक्ष कॉलोनी के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के कारण वैश्विक मंच पर विशेष पहचान बनाई। यह उपलब्धि न केवल स्कूल के लिए, बल्कि भारत के लिए भी गर्व का क्षण है, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिभा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उजागर किया है। ([Click here to read article](#))
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 जुलाई 2025 को त्रिनिदाद और टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें उनकी वैश्विक नेतृत्व क्षमता, भारतीय प्रवासी समुदाय से गहरे जुड़ाव और कोविड-19 महामारी के दौरान मानवीय प्रयासों के लिए दिया गया। बता दें कि पीएम मोदी फिलहाल पांच देशों के दौरे पर हैं और त्रिनिदाद और टोबैगो की यह दो दिन की यात्रा उनका दूसरा पड़ाव है। ([Click here to read article](#))

### Summits and Conferences News

- शहरी शासन और स्थानीय नेतृत्व को सशक्त बनाने की एक ऐतिहासिक पहल में, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 3 जुलाई, 2025 को गुरुग्राम के मानेसर में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। दो दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य तेजी से शहरीकृत भारत में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका को बढ़ाना और संवैधानिक लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण में उनके महत्व को सुदृढ़ करना है। ([Click here to read article](#))
- क्षेत्रीय संपर्क और पर्यटन को बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में, भारत ने 1 जुलाई 2025 को चेन्नई में पहली बार आसियान-भारत कूज वार्ता की मेजबानी की। चेन्नई बंदरगाह पर कूज जहाज एमवी एम्प्रेस पर आयोजित इस वार्ता में सभी 10 आसियान देशों और तिमोर लेस्ते का प्रतिनिधित्व करने वाले 30 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग, टिकाऊ पर्यटन और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना था। ([Click here to read article](#))

### Ranks and Reports

- India has achieved a remarkable 78% reduction in the under-five mortality rate, as reported by the UN IGME हरुन ग्लोबल यूनिफॉर्म इंडेक्स 2025, जो हरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया गया है, वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है। इस वर्ष, दुनिया भर में ऐसे निजी स्टार्टअप की कुल संख्या 1,523 तक पहुँच गई है जिनका मूल्यांकन \$1 बिलियन से अधिक है, जिन्हें "यूनिफॉर्म" कहा जाता है। इन कंपनियों का संयुक्त मूल्य \$5.6 ट्रिलियन है, जो वैश्विक नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में सबसे आगे खड़ी हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि यूनिफॉर्म स्टार्टअप अब वैश्विक अर्थव्यवस्था और तकनीकी प्रगति के प्रमुख वाहक बन चुके हैं। ([Click here to read article](#))

### Sports News

- क्रोएशिया के जाग्रेब में चल रहे सुपरयूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट में भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने रैपिड खिताब जीत लिया है। यह टूर्नामेंट ग्रैंड चैस टूर 2025 का हिस्सा है और गुकेश ने रैपिड फॉर्मेट में 18 में से 14 पॉइंट अर्जित करके खिताब अपने नाम किया। गुकेश ने आखिरी राउंड में अमेरिकी खिलाड़ी वेस्ली सो को 36 चालों में हराकर रैपिड खिताब अपने नाम किया। गुकेश ने टूर्नामेंट में 9 मुकाबलों में से 6 में जीत हासिल की, 2 ड्रॉ रहे और एक में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। गुकेश का शानदार प्रदर्शन उन्हें जन-क्रिस्टोफ डूडा और मैग्नस कार्लसन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों से आगे ले गया है। ([Click here to read article](#))
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति (एनएसपी) 2025 को स्वीकृति दे दी है। देश के खेल परिदृश्य को नया आकार देने और खेलों के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक यह ऐतिहासिक पहल है। नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 का स्थान लेगी और देश को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और वर्ष 2036 ओलंपिक खेलों

सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए एक दूरदर्शी और कार्यनीतिक रोडमैप तैयार करेगी। एनएसपी 2025 को केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ), खिलाड़ियों, खेल विशेषज्ञों और सार्वजनिक हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किया गया है। ([Click here to read article](#))

### Schemes and Committees News

- सामाजिक सुरक्षा कवरेज को व्यापक बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने SPREE 2025 - नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना (Scheme for Promotion of Registration of Employers and Employees) शुरू की है। शिमला में 196वीं ESI कॉर्पोरेशन मीटिंग के दौरान घोषित की गई यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर, 2025 तक चलेगी, जो संविदा और अस्थायी कर्मचारियों सहित पहले से अपंजीकृत प्रतिष्ठानों और श्रमिकों के लिए एक बार पंजीकरण का अवसर प्रदान करती है। ([Click here to read article](#))
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका लक्ष्य विनिर्माण पर विशेष जोर देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा करना है। लगभग ₹1 लाख करोड़ के पर्याप्त परिव्यय के साथ, इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार को बढ़ावा देना, नए रोजगार सृजित करने में नियोक्ताओं का समर्थन करना और भारत के युवा कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है। ([Click here to read article](#))
- भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की एक बड़ी पहल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2025 को ₹1 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ अनुसंधान विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना को मंजूरी दी। यह योजना उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, विशेष रूप से उभरते और रणनीतिक क्षेत्रों में, कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालिक वित्तपोषण की पेशकश करके। कार्यक्रम को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) द्वारा रणनीतिक रूप से निर्देशित किया जाएगा। ([Click here to read article](#))

### Science and Technology News

- हैदराबाद की कंपनी आनंत टेक्नोलॉजीज़ को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। यह प्रोजेक्ट IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र) द्वारा स्वीकृत किया गया है और इसके 2028 में शुरू होने की उम्मीद है। यह सेवा पूरी तरह से भारत में बने उपग्रहों के ज़रिए संचालित की जाएगी। यह कदम अंतरिक्ष-आधारित इंटरनेट सेवाओं में Starlink, OneWeb और Amazon Kuiper जैसे वैश्विक खिलाड़ियों को टक्कर देने की दिशा में भारत का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ([Click here to read article](#))

- हाई-एंड एआई चिप्स में वैश्विक अग्रणी एनवीडिया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनकर इतिहास रचने के लिए तैयार है। गुरुवार को इसका बाजार पूंजीकरण 3.92 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो 26 दिसंबर, 2024 को स्थापित एप्पल के 3.915 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड को पार कर गया। यह न केवल एनवीडिया के लिए, बल्कि पूरी तकनीक और वित्तीय दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। ([Click here to read article](#))
- लद्दाख ने विज्ञान आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। हाल ही में लेह में आयोजित पहले "एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल" का सफल समापन हुआ। यह दो दिवसीय आयोजन लद्दाख पर्यटन विभाग और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA), बेंगलुरु के सहयोग से किया गया, जिसका उद्देश्य लद्दाख को खगोल पर्यटन (Astro Tourism) के प्रमुख गंतव्यों में शामिल करना है। ([Click here to read article](#))

### Important Days News

- दुनिया भर में शनिवार, 5 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस (CoopsDay) मनाया जा रहा है। इस वर्ष का आयोजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष (IYC2025) के दौरान पड़ रहा है। यह दिन इस बात को रेखांकित करता है कि सहकारी संस्थाएं कैसे समावेशी, टिकाऊ और जन-केन्द्रित समुदायों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। CoopsDay का उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांतों को बढ़ावा देना और दुनिया भर में उनके सामाजिक व आर्थिक योगदान को पहचान देना है। ([Click here to read article](#))
- हर साल 4 जुलाई को महान भारतीय संत दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। उन्हें आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना जाता है और उन्होंने हिंदू धर्म और भारतीय मूल्यों को दुनिया तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। ([Click here to read article](#))
- 4 जुलाई, 2025 को, रथ यात्रा के 8वें दिन, ओडिशा के पुरी में सुना बेशा नामक एक भव्य अनुष्ठान होगा। इस विशेष दिन पर, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा जगन्नाथ मंदिर के सामने अपने रथों पर बैठकर स्वर्ण आभूषणों में प्रकट होंगे। इस खूबसूरत और पवित्र आयोजन को देखने के लिए हजारों भक्त आते हैं। ([Click here to read article](#))



## BANK MAHAPACK

for all Bank & Insurance Exams



Selection Ka Saathi

- हर वर्ष 30 जून को विश्व क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पृथ्वी के निकट आने वाले खगोलीय पिंडों (NEOs), विशेष रूप से क्षुद्रग्रहों से उत्पन्न संभावित खतरों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक रूप से इस दिन को मान्यता दी थी। ([Click here to read article](#))
- हर वर्ष 1 जुलाई को भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) दिवस मनाया जाता है, जो देश के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक की शुरुआत की याद दिलाता है। 1 जुलाई 2017 को लागू किए गए GST ने कई अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर एक एकीकृत कर प्रणाली के रूप में पूरे भारतीय बाजार को एक सूत्र में बांध दिया। इस प्रणाली के माध्यम से 'एक राष्ट्र, एक कर' की अवधारणा को साकार किया गया। GST दिवस की शुरुआत 2018 में इसकी पहली वर्षगांठ के रूप में की गई थी, और तब से यह दिन भारत की कर प्रणाली में पारदर्शिता, सरलता और एकरूपता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ([Click here to read article](#))
- देश का सबसे पुराना कमर्शियल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आज 1 जुलाई को 70 वर्ष का हो गया है। इस दिन को एसबीआई शाखाओं में SBI Celebration day के रूप में मनाया जाता है। एसबीआई की जड़ें बैंक आफ कलकत्ता से जुड़ी हैं, जिसकी स्थापना 1806 में हुई थी और बाद में बैंक आफ मद्रास और बैंक आफ बॉम्बे के साथ इसका विलय करके इंपीरियल बैंक आफ इंडिया बना, जो अंततः 1955 में एसबीआई बन गया। ([Click here to read article](#))
- हर वर्ष 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस (CA Day) मनाया जाता है। यह दिन भारत की वित्तीय व्यवस्था और व्यापारिक समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) की स्थापना (1 जुलाई 1949) की स्मृति में मनाया जाता है। यह दिवस उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के योगदान का सम्मान करता है जो वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। ([Click here to read article](#))
- हर साल भारत में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे (National Doctor's Day) मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे देश के उन सभी डॉक्टरों के लिए एक सम्मान के तौर पर मनाया जाता है, जो मानव जीवन को बचाने, रोगों से लड़ने और स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में डॉक्टरों की भूमिका सिर्फ एक मरीज के इलाज तक सीमित नहीं है। बल्कि डॉक्टर समाज में जागरूकता लाने और पुरानी कुरीतियों को तोड़कर नया नजरिया देने का भी काम करते हैं। ([Click here to read article](#))

### Obituaries News

- ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध अभिनेता जूलियन मैकमोहन का 56 वर्ष की आयु में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद फ्लोरिडा में निधन हो गया। वह 'फैंटास्टिक फोर', 'निप/टक', 'चार्म्ड' और 'एफबीआई: मोस्ट वांटेड' जैसे लोकप्रिय टीवी शो और फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। उनकी पत्नी केली मैकमोहन ने यह दुखद समाचार साझा करते हुए उन्हें एक प्यार और जीवन से भरपूर इंसान के रूप में याद किया। जूलियन की मौत से न केवल फिल्म जगत, बल्कि उनके प्रशंसकों के बीच भी गहरा शोक है। ([Click here to read article](#))

**Miscellaneous News**

- पुडुचेरी ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में एक अग्रणी कदम उठाया है, क्योंकि यह भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसने TB स्क्रीनिंग को परिवार गोद लेने के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एकीकृत किया है। यह अभिनव दृष्टिकोण मेडिकल कॉलेजों, छात्रों और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के बीच सहयोग के माध्यम से चलाया जा रहा है। [\(Click here to read article\)](#)
- पुरातत्व और आनुवंशिकी में एक ऐतिहासिक उपलब्धि में, शोधकर्ताओं ने प्राचीन मिस्र के पहले पूर्ण जीनोम को सफलतापूर्वक अनुक्रमित किया

- है। यह खोज न केवल प्राचीन मानव आबादी की हमारी समझ में नए द्वार खोलती है, बल्कि पार-सांस्कृतिक अंतर्क्रियाओं पर भी प्रकाश डालती है। [\(Click here to read article\)](#)
- प्रसिद्ध निवेशक और अरबपति परोपकारी वॉरेन बफेट, जो बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन और सीईओ हैं, ने 27 जून 2025 को कंपनी के स्टॉक्स के रूप में पाँच परोपकारी संस्थाओं को 6 अरब डॉलर का बड़ा दान देने की घोषणा की। यह उनका अब तक का सबसे बड़ा परोपकारी कदमों में से एक है, जिससे 2006 से अब तक उनके कुल दान की राशि लगभग 60 अरब डॉलर तक पहुँच गई है। [\(Click here to read article\)](#)

**Static Takeaways**

क्रमांक	स्थैतिक नाम	स्थैतिक विवरण
1	आरबीआई	राज्यपाल - संजय मल्होत्रा
2	NVIDIA	सीईओ - हुआंग त्सांग
3	SBI	एमडी - चल्ला श्रीनिवासलु शेटी
4	कर्नाटक बैंक	एमडी - श्रीकृष्णन सरमा
5	अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	सीईओ - अमित सिंह
6	SLICE	सीईओ - राजन बजाज
7	रिलायंस जियो	अध्यक्ष - आकाश अंबानी
8	सेल	सीईओ - अमरेंद्र प्रकाश
9	भारत	प्रधानमंत्री - नरेंद्र मोदी राजधानी - नई दिल्ली
10	जापान	प्रधानमंत्री - शिगेरू इशिवा राजधानी - टोक्यो
11	अमेरिका	राष्ट्रपति- डोनाल्ड ट्रम्प राजधानी - वाशिंगटन डी.सी.
12	ऑस्ट्रेलिया	प्रधानमंत्री - एंथनी अल्बानीज़ राजधानी - कैनबरा
13	यूएई	प्रमुख- मोहम्मद बिन जायद अल नायहेन राजधानी - अबू धाबी
14	ओडिशा	सीएम - मोहन माझी राज्यपाल - कंभमपति राजधानी-भुवनेश्वर
15	गुजरात	सीएम-भूपेंद्र पटेल राज्यपाल - आचार्य देवव्रत राजधानी - गांधीनगर
16	यूपी	मुख्यमंत्री - योगी आदित्यनाथ राज्यपाल - आनंदीबेन पटेल राजधानी - लखनऊ

क्रमांक	स्थैतिक नाम	स्थैतिक विवरण
17	कर्नाटक	सीएम - सिद्धारमैया राज्यपाल - थायर चंद गेहलोत राजधानी - बेंगलुरु
18	जम्मू और कश्मीर	मुख्यमंत्री - उमर अब्दुल्ला उपराज्यपाल-मनोज सिन्हा राजधानी - जम्मू
19	बिहार	मुख्यमंत्री - नीतीश कुमार राज्यपाल - आरिफ खान राजधानी - पटना
20	तमिलनाडु	मुख्यमंत्री - स्टालिन राज्यपाल - आर एन रवि राजधानी - चेन्नई

